

गोपेश्वर

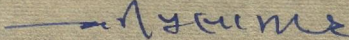
दिनांक १२-२-७५

आदरणीय श्री बीरेन्द्र कुमार जी,

सादर नमस्कार । आज्ञा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न से होंगे । मैं १० फरवरी ७५ को प्रातः की बस से लौट गया था । इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई । डा० स्वामी नाथन्न जी से जब सितम्बर ७४ में भेट हुई थी ~~उन्होंने~~ इस दोत्र के संतरा, माटा के पेड़ों के लिए मिट्टी परीक्षण हेतु ~~क्रि~~ निवेदन ~~विक्र~~ किया था । उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया था, क्या मैं इस सम्बन्ध में उनसे सीधा पत्र व्यवहार कर सकता हूँ ?

आप विदेश यात्रा पर कब तक प्रस्थान कर रहे हैं !

आपका

  
( चण्डी प्रसाद चहबराट )

सेवा में,

श्री बीरेन्द्र कुमार जी, प्रोफेसर, बनस्पति विज्ञान,  
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट, नई-दिल्ली ।

Phone : 83  
Tel : Sarvodaya  
Gopeshwar-Chamoli  
(Uttarakhand)

## दशोली ग्राम स्वराज्य संघ

DASHOLI GRAM SWARAJYA SANGH

(खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित)

चण्डी प्रसाद भट्ट,

फोन । ८३  
तार : सर्वोदय  
गोपेश्वर-चमोली  
( उत्तराखण्ड )

PIN : 246401

दिनांक/Date २२-११-८०

आदरणीय डा० साहब,

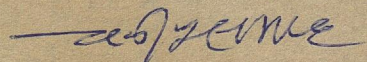
इस पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि भिजवा रहा हूँ । अल्लानन्दा और उसकी सहायक नदियों के संवेदनशील जलागम क्षेत्र में पड़ने वाले बदरी-केदार वन प्रभागों के संवर्धन व सुरक्षा में आपने सदा ही गहरी रुचि ली है ।

मुझे पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री को लिखे गये इस पत्र के विषय में भी आप अपने स्तर पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे । ताकि इस संवेदनशील क्षेत्र में सरकार की शक्ति और जन शक्ति के सहयोग से व्यापक वनीकरण का कार्यक्रम चलाया जा सके ।

संलग्न- प्रधानमंत्री को लिखा पत्र,

२६ फरवरी १९७१ के नेशनल हेराल्ड  
लखनऊ संस्करण में छपे समाचार की प्रति,

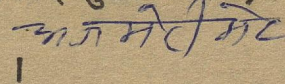
विनीत

  
( चण्डी प्रसाद भट्ट )

सेवा में,

डा० वीरेंद्र कुमार जी,

डा० जाकिर हुसेन कालेज,

नई देहली । 

Phone : 83  
Tel : Sarvodaya  
Gopeshwar-Chamoli  
(Uttarakhand)

दशोली ग्राम स्वराज्य संघ  
DASHOLI GRAM SWARAJYA SANGH  
(खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित)

फोन । ८३  
तार : सर्वोदय  
गोपेश्वर-चमोली  
( उत्तराखण्ड )  
PIN : 246401

दिनांक/Date २२ नवम्बर ८०

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

कपड़ी प्रपाद पट्ट का प्रणाम स्वीकारक  
करें। सुदूर हिमाचल के सेवेदनशील क्षेत्र में बसे वीर कुल सामाजिक  
काम करने वाले हम लोग आपकी इस बात के लिये धन्यवाद देना  
चाहते हैं कि आपने पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन तथा जनवासियों की  
समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है। इसी से उत्साहित होकर हम  
आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक अत्यन्त सेवेदनशील  
भाग के संरक्षण के लिये लींचा चाहते हैं। इस क्षेत्र में कानों की रक्षा  
के लिये कलाये गये "चिपको" आन्दोलन तथा राज्य सरकार की  
समकक्षारी के मिले-जुले प्रयागों से लगभग १५,००० हेक्टेयर में कानों के  
व्यावसायिक व व्यापारिक कटान पर सन् १९७६ के १९८६ तक रोक  
ला चुकी है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र बदरीनाथ-कैदारनाथ का प्रभागों में  
गंगा की मुख्य धारा बलानन्दा के जलमग का क्षेत्र है।

गांव के लोगों की जागृति से बन्ना चिपको आन्दोलन और  
उसके कारण उग्रप्रो शासन द्वारा डा० बीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में  
गठित "रेणी चिपको आन्दोलन अध्ययन समिति" की संस्तुतियों  
तथा शासन की दूरदर्शिता से देश में पहली बार कानों के संरक्षण  
की दिशा में इतना बड़ा प्रतिबन्ध ला सका। यह हम सबके लिये  
सौभाग्य की बात है। पर अभी भी इस सेवेदनशील क्षेत्र का थोड़ा सा  
भाग कटाई के लिये जुला है।

बलानन्दा की सहायक नदियों का यह तीला ढालदार जलमग  
बहुत ही सेवेदनशील है। यह क्षेत्र प्रति वर्ष भूस्खलन तथा भूजलरण  
को लातार न्योता देता रहता है। स्वयं सरकार ने इस बात को  
स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में बसे वाले लगभग ४०० गांवों को  
इन सहायक नदियों तथा नालों से खतरा रहता है और इन गांवों के

के क्षेत्र, मजान तथा गौशालायें कभी भूस्वल्प का शिकार हो सकती है।

लेकिन केवल स्थानीय स्तर ही नहीं है। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के दुष्परिणाम दूर नीचे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। ऐसे दुष्प्रभाव का एक संकेत सन् १९७० में जायी बलकनन्दा की बाढ़ से जुकी है। १९७० की इस बाढ़ का केन्द्र गहड़गाँव तथा कण्ठिगाँव के बीच फैला ६० किलोमीटर लम्बा क्षेत्र था, इस क्षेत्र का जलागम बुंवारी पर्वत है। उस दुर्भाग्यशाली दिन को नदी में बड़ी ताद (सिद्ध) की मात्रा का बुरा बहार स्थानीय क्षेत्रों और ज्वालामुखी की सीमाओं को तोड़ते हुए ३०० किलोमीटर दूर हरिद्वार तक पहुँचा था। हरिद्वार से निम्नलिखित निकलने वाली लम्बा २०० फुट चौड़ी बगर गंगा नहर इस सिद्ध के कारण १० किलोमीटर तक रेत से भर गयी थी। इस वकह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के १ लाख ५० हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मछियों तक सिंचाई नहीं हो स्यापायी थी।

आप जब पिछली बार अक्टूबर १९७६ में बदरीनाथ जाते हुए गोपेश्वर जायी थी, तब हमारी संस्था "पशोली ग्राम स्वराज्य संघ" ने इस परिस्थिति से सम्बन्धित कुछ सामग्री आपको भेंट की थी।

इस संवेदनशील क्षेत्र में १५२००० हेक्टेयर में कनों के कटान पर रोक लगाने से यहाँ के उबड़ते पहाड़ों को काफी हद तक बराम मिला है। इसी उत्साहित होकर हमारी छोटी सी संस्था पशोली ग्राम स्वराज्य संघ ने टंगसा ग्राम सेवा संस्थान जैसी अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से यहाँ फिर से बड़े पैमाने पर पेड़, घास बादि लगाने का काम गाँव के लोगों के सहयोग से उठाया है। इस काम में कस्तुरी शासन के सम्बन्धित विभाग भी सहयोग दे रहे हैं।

लेकिन जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ। इस संवेदनशील भाग का कुछ भाग अभी भी कटान के लिये जुड़ा है। वाश्चर्य की बात तो यह भी है कि सन् १९७० की भयंकर बाढ़ को देखते हुए भारत सरकार ने ज्वालामुखी क्षेत्रों में बलकनन्दा और इस उसकी समस्त सहायक नदियों के जलागम क्षेत्रों में कनों का कटान रोकने तथा तीव्रता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का आदेश दिया था। इस आशय का समाचार २६ फरवरी १९७१ को नेशनल हेराल्ड के एक संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इन लोगों ने इस घोषणा के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री को सन् ७४ में इस बात की बार-बार याद भी दिलायी थी। लेकिन न जाने क्यों यह आदेश पूरा नहीं किया जा सका।

सू. ७३-७४ में बड़े बान्धोज तथा उत्तरी भागों की जांच के लिये गठित उपरोक्त  
वर्णित समिति की संस्तुतियों के कारण इस क्षेत्र के एक बड़े भाग में कर्कों का  
काटना रोक रखा गया है। निवेदन है कि इस क्षेत्र के बचे हुए भाग में भी काटान  
रोका जाये तथा कदरी-कदार का प्रभागों के बन्धनत वाले वाले पूरे हिस्से को  
आराम दिया जाये।

मे बाफलों काश्ताक केना चाहता हूं कि स्थानीय जन शक्ति  
बौर सरकारी कर्मचारी का क दायरा कर बढ़े का बौर इन दोनों का  
प्रभागों में स्थानीय जन वासियों के एक-दूसरों को बौर स्थानीय छोटे उद्योगों  
की करतों को छोड़, यदि व्यावसायिक व व्यापारिक कटान पर रोक लाती है  
तो फिर इन सब छोटी-छोटी गैर सरकारी संस्थाएं जालन के सहयोग से  
सब उभरते जा रहे हलके को फिर से उरा-भरा कानन के महत्वपूर्ण काम में  
जुट जायें।

बाफलों का कताते हुये हमें यह बुझी हो रही है कि बाज इस  
कमजोर प्रतिबन्ध के कारण भी इन दोनों का प्रभागों में बने गांवों में पुस्तक,  
पुनारण के रोकने तथा सामाजिक वाणिजी की दृष्टि से पैड़ लाने का कार्यक्रम  
तेजी से चल रहा है। अनेक गांव की महिलायें, युवक, गीनार  
विश्वविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय से ऊपर प्राथमी स्तर के छोटे-छोटे  
कियाधी भी शामिल हो रहे हैं। इसलिये मे सब बार बाफते फिर निवेदन  
करना चाहता हूं कि कवासियों के परम्परागत एक-दूसरे तथा व्यापारिक  
स्थानीय छोटे उद्योगों की करत को छोड़ कर सब पूरे संवेदनशील क्षेत्र के  
के कर्कों में व्यापारिक बौर व्यावसायिक कटान पर पूरी तरह से रोक लाने  
की कृपा करें।

किरीट

सेवा में,

माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी,  
प्रधानमंत्री,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली।

— 26/4/68 —  
( कण्ठी प्रसाद मूढ )